



2026:AHC:22545-DB

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जेल अपील संख्या - 311/2018

जगन्नाथ

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी के अधिवक्ता : देवेन्द्र प्रताप सिंह, जेल से

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. यह आपराधिक अपील, मथुरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3 द्वारा एसटी संख्या 24 /2013 में 25.02.2017 को दिए गए फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत, पुलिस थाना गोवर्धन, जिला मथुरा से संबंधित है। इस फैसले में, माननीय न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी; साथ ही, यह निर्देश भी दिया गया था कि यदि अपीलकर्ता जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई; इसमें भी यह शर्त थी कि यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. हालाँकि, यह निर्देश दिया गया था कि ये दोनों सज़ाएँ एक साथ (समवर्ती रूप से) चलेंगी।

संक्षिप्त तथ्य

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि मधुसूदन के बेटे कृष्ण दास, जो बरसाना, जिला मथुरा के निवासी हैं (जिन्हें इसके बाद "प्रथम सूचनाकर्ता" कहा जाएगा), ने थाना गोवर्धन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बहन मीरा के घर में एक हैंडपंप है। अनंत दास के शिष्य जगन्नाथ उस हैंडपंप से पानी भर रहे थे, जिसके कारण पानी गंदा (कीचड़ वाला) हो गया। जब उनकी बहन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उसने हैंडपंप का पानी गंदा क्यों कर दिया, तो उसने बहन को गालियां देना शुरू कर दिया। जब अशोक पाल, जो अरविंद हलधर के घर में काम कर रहे थे, ने इस मामले में बीच-बचाव करने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की कोशिश की, तो आरोपी ने जान से मारने के इरादे से अशोक पाल की छाती पर चाकू से वार कर दिया। उसने प्रथम सूचनाकर्ता पर भी जान से मारने के इरादे से उसके हाथ पर हमला किया। हमले के बाद, आरोपी अपने शिष्य के साथ वहां से भाग गया। अशोक पाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना 09.08.2012 को सुबह 10:00 बजे हुई थी।

4. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर, थाना गोवर्धन में केस क्राइम नंबर 469/2012 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत एक 'चिक (प्राथमिकी)' दर्ज की गई, जिसे सुबह 11:00 बजे रिपोर्ट नंबर 29 के माध्यम से (सामान्य डायरी) में दर्ज किया गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, अवर निरीक्षक डी.एल. पाल, जो उस समय थाने में मौजूद थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव का '(पंचनामा)' किया और पोस्टमार्टम जांच से संबंधित कागजात तैयार किए। उन्होंने मृतक का शव कांस्टेबल पुष्पपाल सिंह और कांस्टेबल आशाराम को पोस्टमार्टम जांच करवाने के लिए सौंप दिया।

6. पी.डब्ल्यू-4, डॉ. संजीव गुप्ता ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. बाएं निप्पल के ठीक नीचे 2 सेमी x 1 सेमी गहरा कटा हुआ घाव, जिसका निचला सिरा छाती के बीच की लाइन से 5 सेमी अंदर और ऊपरी सिरा छाती के बीच की लाइन से 6 सेमी अंदर है।

2. छाती के बाईं ओर 2 सेमी आगे, 3 सेमी x 1 सेमी स्किन में गहरा कटा हुआ घाव।

डॉक्टर की राय में, मौत का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप हुआ सदमा और रक्तस्राव था।

7. घायल कृष्ण दास को कांस्टेबल 2192, तहसीलदार सिंह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ पी.डब्लू- 7, डॉ. राजेंद्र सिंघल, चिकित्सा अधीक्षक ने उनकी जाँच की; जाँच के दौरान उन्होंने घायल कृष्ण दास के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

“हाथ के बाईं ओर 1 सेमी x 2 सेमी x 3 सेमी गहरी कटी हुई चोट।”

डॉक्टर की राय में, चोट सामान्य प्रकृति की थी और किसी धारदार हथियार से लगी थी।

8. मामले की जाँच पी.डब्लू- 6, राघवेंद्र सिंह ने शुरू की, जो गोवर्धन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और घटनास्थल का नक्शा (साइट प्लान) तैयार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने आरोपी के बताने पर वह चाकू

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बरामद किया जिसका इस्तेमाल अपराध करने में किया गया था। उन्होंने आरोपी के खून से सने कपड़े, सादी और खून से सनी मिट्टी भी जमा की और उनके मेमो तैयार किए। जाँच पूरी होने के बाद, जाँच अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

9. चूंकि यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहाँ मामला एसटी संख्या 24/2013 के रूप में पंजीकृत किया गया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, मथुरा ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए, जिन्हें उसे पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया।

10. अपीलकर्ता का दोष सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की जाँच की; इनमें से पी.डब्लू- 1 कृष्ण, पी.डब्लू - 2 मीरा दासी और पी.डब्लू- 3 प्रदीप दास 'तथ्य के गवाह' (घटना के प्रत्यक्षदर्शी) हैं, जबकि पी.डब्लू- 4 डॉ. संजीव गुप्ता (जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया), पी.डब्लू- 5 सतीश चंद्र (जिन्होंने 'चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट' तैयार की), पी.डब्लू- 6 राघवेंद्र सिंह (मामले के जाँच अधिकारी) और पी.डब्लू- 7 डॉ. राजेंद्र सिंघल (जिन्होंने घायल व्यक्ति की जाँच की) 'औपचारिक गवाह' हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया; आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की इच्छा व्यक्त की।

12. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, मथुरा ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन, मूल्यांकन और सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थी को, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, दोषसिद्ध किया और दण्डित किया।

13. अतः, यह अपील प्रस्तुत है।

अपीलार्थी की ओर से निवेदन

14. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सर्वप्रथम यह निवेदन करते हैं कि वे अपनी बहस को केवल इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि दण्ड को धारा 302 से धारा 304 भारतीय दंड संहिता में परिवर्तित कर दिया जाए; और वे यह निवेदन करते हैं कि मृतक-अशोक पाल तथा घायल कृष्ण दास को अपीलार्थी द्वारा पहुँचाई गई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए, यह मामला धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता के दायरे से बाहर नहीं जाएगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

15. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री नीरज कुमार तिवारी ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त ने मृतक की छाती पर चाकू से चोट पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई; और चूंकि कोई गंभीर या अचानक उकसावा नहीं था, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है और सज़ा सुनाई है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया, और मामले के समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किसी भी निर्णय में विधि का ऐसा कोई पूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है कि यदि किसी मामले में केवल एक ही प्रहार किया गया हो तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति के आशय को निर्धारित के लिए चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं होती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम विचाराधीन बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना चाहेंगे, जहाँ तक अपीलकर्ता का संबंध है।

19. **जगतर सिंह बनाम पंजाब राज्य** (1983) 2 एससीसी 342 के मामले में, आरोपी ने अचानक आवेश में आकर मृतक की छाती पर चाकू से वार कर दिया। यह चोट जानलेवा साबित हुई। डॉक्टर ने राय दी कि सामान्य परिस्थितियों में, यह चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि झगड़ा बहुत मामूली प्रकृति का था, और ऐसे मामूली झगड़े में भी अपीलकर्ता ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया और छाती पर वार किया। इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि आरोपी को कम से कम इस बात का ज्ञान तो था ही कि वह ऐसी चोट पहुँचाने वाला है जिससे मौत होने की संभावना है। न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से बदलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत कर दिया और आरोपी को पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

20. **के. रामकोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, 1986 सीआर.एल.जे. 680 के मामले में, आरोपी और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हो गया, और मृतक ने आरोपी को गंभीर परिणामों

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की धमकी दी। आरोपी ने चाकू से मृतक पर वार किया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के तहत दोषी ठहराया।

21. **सुरिंदर कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़**, (1989) 2 एससीसी 217 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अचानक हुए झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति आवेश में आकर पास में मौजूद कोई हथियार उठा लेता है और उससे चोटें पहुँचाता है, जिनमें से केवल एक चोट ही जानलेवा साबित होती है, तो वह उस अपवाद का लाभ पाने का हकदार होगा, बशर्ते उसने क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्य न किया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ऐसी स्थिति में, घटना के दौरान लगी चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह थी कि घटना अचानक और बिना किसी पूर्व-योजना के हुई लड़ाई के परिणामस्वरूप घटी थी, और अपराधी ने निश्चित रूप से गुस्से के आवेश में आकर ही कार्य किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के प्रावधान पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"..... इस अपवाद का लाभ उठाने के लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए, वे हैं: (i) यह एक अचानक हुई लड़ाई थी; (ii) इसमें कोई पूर्व-नियोजन नहीं था; (iii) यह कार्य आवेश में आकर किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था और न ही उसने क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्य किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है, और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाया या किसने हमला शुरू किया। घटना के दौरान लगे घावों की संख्या कोई

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना अचानक और बिना किसी पूर्व-नियोजन के हुई हो, और अपराधी ने गुस्से के आवेश में आकर कार्य किया हो। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो और न ही उसने क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्य किया हो। जहाँ, अचानक हुए झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति उस क्षण के आवेश में आकर अपने हाथ में मौजूद कोई हथियार उठा लेता है और चोट पहुँचाता है—जिनमें से कोई एक चोट जानलेवा साबित होती है—तो वह इस अपवाद का लाभ पाने का हकदार होगा, बशर्ते उसने क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्य न किया हो।"

22. **वी. श्रीधरन बनाम केरल राज्य**, एआईआर 1992 एससी मामले में, आरोपी ने अचानक हुई कहा-सुनी के दौरान गुस्से में आकर मृतक का कुछ दूर तक पीछा किया और फिर उसे एक जानलेवा वार किया; इस मामले में यह माना गया कि यह पूरी घटना एक लगातार चलने वाली कड़ी थी। इसलिए, आरोपी की सज़ा को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-I भारतीय दंड संहिता के तहत कर दिया गया।

23. **भैरा बनाम राजस्थान राज्य**, 2000 एससीसी (क्री) 1230 मामले में, आरोपी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर अचानक चाकू निकाला और मृतक की छाती पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मिली सज़ा को रद्द कर दिया, और

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसके बजाय उसे धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई।

24. **मोची राजू बनाम गुजरात**, जेटी 2001 (10) एससी 398 मामले में, आरोपी अपीलकर्ता और मृतक के बीच लड़ाई शुरू हो गई और झगड़े के दौरान अपीलकर्ता ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मृतक की छाती पर एक वार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 304 भाग-II के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए, उसे पाँच साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

25. **सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य** (2002) 3 एससीसी 327 मामले में, अपीलकर्ता ने मृतक के शरीर के एक बेहद संवेदनशील हिस्से पर भाले से दो वार किए, जो कि प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। हाई कोर्ट ने यह माना कि अपीलकर्ता ने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया था। हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण को पलटते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मौत का कारण बनने वाली सभी जानलेवा चोटों को, भारतीय दंड संहिता के धारा 300 के अपवाद 4 के प्रयोजनों के लिए, क्रूर या असामान्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में, जहाँ घायल व्यक्ति के गिर जाने के बाद, अपीलकर्ता ने उसकी असहाय स्थिति का फायदा उठाकर उस पर कोई और चोट नहीं पहुँचाई, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26. **सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**, (2002) 3 एससीसी 327 मामले में, अपीलकर्ता ने मृतक के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर भाले से दो बार किए थे, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। हाई कोर्ट ने यह माना कि अपीलकर्ता ने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया था। हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण को पलटते हुए, इस कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मृत्यु का कारण बनने वाली सभी जानलेवा चोटों को, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के प्रयोजनों के लिए, क्रूर या असामान्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामलों में, जहाँ घायल व्यक्ति के गिर जाने के बाद, अपीलकर्ता ने उस पर कोई और चोट नहीं पहुँचाई, जबकि वह एक असहाय स्थिति में था, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की: “...सभी जानलेवा चोटें, जिनके कारण मृत्यु हो जाती है, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ न देने के उद्देश्य से क्रूर या असामान्य नहीं कहा जा सकता। चोटें लगने और घायल व्यक्ति के गिर जाने के बाद, यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता ने उस व्यक्ति पर कोई और चोट पहुँचाई हो, जबकि वह एक असहाय स्थिति में था। यह साबित होता है कि अचानक हुए झगड़े और उसके बाद हुई लड़ाई के दौरान, गुस्से की आवेश में आकर, आरोपी—जो भाले से लैस था—ने बेतरतीब ढंग से चोटें पहुँचाई, और इस प्रकार उसने कोई क्रूर या असामान्य कार्य नहीं किया।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



27. **षण्मुगम बनाम तमिलनाडु राज्य**, एआईआर 2003 एससी 200 के मामले में, आरोपी ने एक मामूली झगड़े को लेकर मृतक के पेट और सीने में भाले से वार किया। पीड़ित की रक्त संक्रमण के कारण एक सप्ताह बाद मृत्यु हो गई। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के तहत दंडित किया गया।

28. **घापू यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2003) 3 एससीसी 528 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि गुस्से की आवेश में, भावनाओं को शांत होने का कोई समय नहीं मिलना चाहिए; और उस मामले में, न्यायालय के समक्ष मौजूद पक्षों ने शुरुआत में हुई मौखिक कहा-सुनी के कारण स्वयं को अत्यधिक क्रोधित कर लिया था। यह घटना बिना किसी पूर्व-योजना के अचानक हुए झगड़े का परिणाम होने के अलावा, कानून यह भी अपेक्षा करता है कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो, और न ही उसने कोई क्रूर या असामान्य कार्य किया हो, ताकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ प्राप्त करने का दावा कर सके। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि लड़ाई अचानक हुई थी या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा।”

29. **पुलिचेरला नागराजू @ नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** (2006) 11 एससीसी 444 के मामले में, माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"अतः, न्यायालय को 'आशय' के मुख्य प्रश्न का निर्णय अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि मामला धारा 302 के अंतर्गत आता है, या धारा 304 भाग I के, अथवा धारा 304 भाग II के अंतर्गत। अनेक छोटी-मोटी या तुच्छ बातें - जैसे फल तोड़ना, मवेशियों का भटक जाना, बच्चों का झगड़ा, कोई कटु शब्द कहना, या यहाँ तक कि कोई आपत्तिजनक नज़र डालना - भी कहा-सुनी और आपसी झड़पों का रूप ले सकती हैं, जिनका परिणाम अंततः मृत्यु के रूप में सामने आ सकता है। ऐसे मामलों में, प्रतिशोध, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई 'आशय' ही न हो। हो सकता है कि कोई पूर्व-नियोजन ही न हो। वास्तव में, हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की आपराधिकता का तत्व भी मौजूद न हो।"

30. सुधाकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012)8 एससी 289 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"प्रकट किए गए तथ्यों के विवरण को देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि अपीलकर्ता के मन में मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई पूर्व-नियोजित इरादा था। पी. डबल्यू-1 के बयान को ध्यान में रखते हुए—कि मृतक शराब के नशे में था और जब भी वह शराब के नशे में होता था, तो वह घर का सामान फेंकने लगता था और घर में हंगामा खड़ा कर देता था—यह एक ऐसा कारक था जिसने अपीलकर्ता के मन में आवेश उत्पन्न कर दिया; अपीलकर्ता, जो एक पिता था, अपने बेटे के ऐसे व्यवहार को सहन करने की स्थिति

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में नहीं था, जिसका शराब के नशे में किया गया दुर्व्यवहार उसके लिए एक मानसिक यंत्रणा बन गया था। इसलिए, परिणामों की परवाह किए बिना—हालांकि किसी क्रूर तरीके से नहीं—अपीलकर्ता ने एक ही बार किया, जिससे दुर्भाग्यवश मृतक के महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर क्षति पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित और सिद्ध पाया गया अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के 'प्रथम भाग' के अंतर्गत लाया जा सकता है। तदनुसार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, हम उसमें केवल यह संशोधन कर रहे हैं कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के 'प्रथम भाग' के अंतर्गत माना जाए। जहां तक अपीलकर्ता पर अधिरोपित दंडादेश का प्रश्न है—चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के 'प्रथम भाग' के अंतर्गत होनी चाहिए—और अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भोगी जा चुकी कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हमने 'कारावास प्रमाण पत्र' से यह पाया है कि अपीलकर्ता 12.07.2004 से जेल में है और उसकी आयु 60 वर्ष है; पी. डबल्यू.-1, जो अपीलकर्ता की पत्नी है, अब बिल्कुल अकेली रह गई है; और अपीलकर्ता आठ वर्ष से अधिक समय तक कारावास भोग चुका है। अतः हम यह निर्णय देते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भोगी जा चुकी कारावास की अवधि ही उसके लिए पर्याप्त दंड होगी—इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए अर्थदंड और उसके व्यतिक्रम की स्थिति में दिए जाने वाले अतिरिक्त कारावास

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का दंड यथावत लागू रहेगा। अपील, अपीलकर्ता पर आरोपित अपराध और अधिरोपित दंडादेश में उपर्युक्त संशोधनों के साथ, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।”

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दायरे में आता है या धारा 304 के।

32. पी.डब्लू- 1, जो इस मामले का प्रथम सूचनादाता है, ने अपने बयान में कहा है कि अभियुक्त के साथ उसका एक शिष्य भी था, जिसे वह पहचानता है, लेकिन उसका नाम नहीं जानता। उसने आगे कहा कि उसकी बहन ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उस इलाके में कोई हैंडपंप नहीं था। इस गवाह ने आगे कहा कि मृतक को बचाते समय उसे चोटें आईं। पी.डब्लू- 1, कृष्ण, जो इस मामले का प्रथम सूचनादाता और घायल व्यक्ति है, के बयान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसे चाकू मारने की कोशिश की थी, जो चूक गया और मृतक की छाती पर जा लगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वह वार शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर लक्षित नहीं था। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह घटना हैंडपंप से पानी भरने और हैंडपंप को गंदा करने जैसे एक बहुत ही मामूली मुद्दे पर हुई थी। इसमें कोई पूर्व-नियोजन नहीं था और यह कृत्य आवेश में आकर किया गया था। साथ ही, किसी भी गवाह ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि घायल व्यक्ति के गिर जाने के बाद, जब पीड़ित असहाय स्थिति में था, तब

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसे कोई और चोट पहुंचाई हो; यह इस बात का संकेत है कि अभियुक्त ने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था। पी.डब्लू-1, कृष्ण, जो इस मामले का प्रथम सूचनादाता है, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि अशोक, हलधर के घर पर काम करता था, जो स्वयं घटनास्थल पर आया और विवाद में शामिल हो गया। पी.डब्लू-2, श्रीमती मीरा दासी ने अपने बयान में यहाँ तक कहा है कि अभियुक्त एक सप्ताह पहले ही गाँव में आया था और एक किराए के मकान में रह रहा था। इसके अतिरिक्त, गवाहों के बयानों में मृतक और अपीलकर्ता के बीच किसी भी प्रकार की पुरानी दुश्मनी का कोई ज़िक्र नहीं है।

33. हमारी राय में, इन सभी परिस्थितियों के सामूहिक प्रभाव के आधार पर, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ मिलना चाहिए।

34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए उपरोक्त कानूनी सिद्धांत को देखते हुए, और मृतक तथा घायल व्यक्ति को लगी चोटों की प्रकृति और ऊपर बताए गए हालात को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि मृत्यु आरोपी-अपीलकर्ता के ऐसे कृत्यों के कारण हुई थी, जो इस इरादे से किए गए थे कि ऐसी शारीरिक चोट लगे जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; और इसलिए, यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय, पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के दायरे में आएगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



35. उपरोक्त समग्र परिदृश्य को देखते हुए, अपीलकर्ता जगन्नाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह न्यायालय आजीवन कारावास की सज़ा का समर्थन करने में संकोच महसूस करता है। तदनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द किया जाता है; इसके बजाय, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के तहत दोषी ठहराया जाता है और आठ वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराए जाने के फैसले की पुष्टि की जाती है। बताया गया है कि अपीलकर्ता 10.08.2012 से जेल में है। उसे तत्काल रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो और उसने आठ वर्ष की संशोधित सज़ा पूरी कर ली हो।

36. परिणामस्वरूप, मथुरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03 द्वारा दिनांक 25.02.2016 को पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ, इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

37. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति के साथ निचली अदालत का रिकॉर्ड संबंधित न्यायालय को अनुपालन हेतु प्रेषित करे।

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति) (चन्द्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 28.01.2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इशरत

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"